क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लौह अस्यक के इतने भारी भंडार उपलब्ध होने के आधार पर बस्तर जिले में एक लघु लौह संयंत्र लगाने का कोई प्रयास कर रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां,

(ग) 60–65 लाख टन प्रतिवर्ष के निर्यात के वर्तमान स्तर के पश्चात भी लौह अस्यक का प्रचुर भण्डार देशीय खपत के लिए उपलब्ध रहेगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंन्ट कारपोरेशन ने बस्तर जिले में लघु लोहा कारखाना स्थापित करने की कोई योजना नहीं बनायी है।

Import of Fertilisers

2060. PROF C. LAKSHMANNA: Wil the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to continue the import of fertilisers from the rupee trade conutries in spite of the glut of fertilisers in the country; and

(b) if so, what are the reasons therefor and the circumstances under which the import of fertilisers from the rupee trade countries is necessary?

THE MINISTER OF STATE IN DEPARTMENT OF FERTILISERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) and (b) The plan for import of urea and di-amonium phosphate (DAP) during the year 1987-88 has not yet been finalised. In case any of these materials are required to be imported to meet the demand for fertilisers from the farmers; it may have to be imported preferably from rupee-payment countries. Muriate of Potash is not available indigenously and part of it is planned to be imported from rupee payment areas during 1987-88.

Rehabilitation of Fertiliser Plants of IFFCO

2061. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any plan to rehabilitate the fertiliser plants of the Indian Farmers Fertiliser Corporation Limited;

(b) if so, the estimated investment and whether the World Bank has agreed to finance part of the foreign exchange requirements of the project; and

(c) if so, the amount of foreign exchange aid expected to be received from the World Bank?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU). (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The estimated investment for rehabilitating the fertiliser plants of IFFCO is Rs. 129.20 crores, out of which the World Bank has agreed to finance Rs. 49.50 crores in foreign exchange.

Decline in Fertilizer Production

2062. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the continuous crises in the fertilizer industry in the country resulting in substantial shortfall in the production targets and glut in fertilizers;

(b) if so, what is the precentage of decline, if any, in the fertiliser output during the last one year as against the total production capacity and what is the estimated stock of fertilisers accumulated due to glut:

(c) what are the main factors responsible for the present situation; and

(d) what remedial measures are being contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) and (b) There is no crisis in the fertilizers industry leading to shortfall in production targets. The indigenous production of nitrogenous and phosphatic fertilizers during 1986-87 is expected to match the target of 69.50 lakh tonnes of nutrients, which is higher than the production of 57.50 lakh tonnes during the previous year as against the target of 57.34 lakh tonnes.

There has, however, been a build up of the stocks of the fertilizer nutrients of about 30.93 lakh metric tonnes as on 1.2-87.

(c) The build up of stocks is mainly due to low consumption on account of unfavourable weather conditions in many parts of the country.

(d) With a view to balancing demand and supply, the import of fertilizers during 1986-87 has been curtailed by about 6.3 lakh tonnes of nutrients. It has also been decided not to import any urea and DAP fertilizers, during the first quarter of 1987-88. Besides, the position is being reviewed regularly in the light of consumption trends.

सस्य वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाएं

2063. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिलास्तरीय सस्य-वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों की संख्या कितनी है और जिन संस्थाओं द्वारा उन्हें चलाया जा रहा है उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या उनके कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो उनकी वित्तीय स्थिति, व्यय, कृषि वैज्ञानिकों के सम्पूर्ण संवर्ग की समीक्षा कार्य क्षेत्र केन्द्र को चलाने वाली संस्था का नाम और उसकी स्थिति, और क्या इसके लिये आवंटित राशि को किसी अन्य कार्य पर खर्च किया जा रहा है, आदि के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) बिहार में इन केन्द्रों की स्थिति क्या है और क्या यह सच है कि दियारा क्षेत्र के संबंध में मुंगेर में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं में कृषि वैज्ञानिकों के सभी पद अभी तक भरे नहीं गए है; और जो वैज्ञानिक पहले से वहां काम कर रहे थे, वे भी छोड़ कर चले गए है; और

(घ) क्या किसी भी क्षेत्र में न तो कोई सफलता मिल पाई है और न ही आवंटित धन को व्यय किया गया है, यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) अखिल भारतीय समन्वित सदस्य अनुसंधान प्रयोजना के दो घटक है:

(i) फसल प्रणाली अनुसंधान परीक्षण 40 स्थानों पर।

(ii) किसानों के खेंतो में परीक्षण 42 जिलों में ।

इनके स्थानों और कार्यान्वयन करने वाले संस्थानों/संस्थाओं के ब्यौरे विवरण-I और विवरण-ii में दिये गये हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) जी हां, श्रीमन इस प्रायोजना के कार्यकरण की समीक्षा परिषद द्वारा नियुक्त पुनरीक्षण दल द्वारा की गयी थी। इस समिति ने इस प्रायोजन को उपयुक्त प्रकार से सुदृढ़ करने के लिए इसके वैज्ञानिक तकनीकी प्रशासनिक और वित्तीय घटकों की बारीकी से जांच की । इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को परिषद के शासी निकाय द्वारा दिसम्बर 1983 में पुष्ट किया तदनुसार इस प्रायोजना के अन्तर्गत किये जा रहे अच्छ गुणवत्ता-युक्त कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रायोजना के स्तर को बढ़ाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रयोजना निदेशालय किया गया है ।

आबंटित राशि प्रति वर्ष परिषद द्वारा उपरोक्त (क) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार अनुलग्नक में दिये गये केन्द्रों में